आंगनवाड़ी सुधार पर भी ध्यान दें

भारत डोगरा

इन दिनों मिड-डे मील में सुधार करने की जो व्यापक चर्चा हुई है, उसमें आंगनवाड़ी के सुधार के मुद्दे को भी शामिल करना चाहिए। आंगनवाड़ी या समग्र बाल विकास सेवा विश्व के सबसे विस्तृत बाल व मातृ पोषण व देखरेख कार्यक्रम के रूप में पहचान रखती है और बहुत दूर-दूर के गांवों में पहुंची भी है। अनुमान है कि यह कार्यक्रम 14 लाख बस्तियों तक पहुंच चुका है, पर उचित सुविधाओं के अभाव में अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रहा है।

महा लेखा परीक्षक द्वारा 13 राज्यों के 67 ज़िलों में सर्वेक्षण पर आधारित रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन 2730 आंगनवाड़ी केंद्रों से जानकारी एकत्र की गई, उनमें से 61 प्रतिशत के पास अपनी बिल्डिंग नहीं थी। 40-65 प्रतिशत के पास खाना पकाने, खाद्य सामग्री स्टोर करने व बच्चों की विभिन्न गतिविधियों के लिए अलग जगह नहीं थी। 52 प्रतिशत केंद्रों में अपना शौचालय नहीं था। 32 प्रतिशत में पेयजल सुविधा नहीं थी। बच्चों व माताओं का वज़न करने की मशीन क्रमशः 26 व 58 प्रतिशत आंगनवाड़ी केंद्रों में मौजूद नहीं थी। 33-49 प्रतिशत केन्द्रों के पास दवा का किट नहीं था। शिक्षा के किट 41-51 प्रतिशत बच्चों को ही उपलब्ध हुए।

स्पष्ट है कि आंगनवाड़ी को बेहतर वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने चाहिए और इनके बेहतर उपयोग की भी अभी बहुत गुंजाइश है। समय-समय पर आंगनवाड़ी के बजट के उचित उपयोग न होने के समाचार मिलते रहे हैं। मसलन, उ.प्र. में एक शराब व खनन माफिया के व्यक्ति को आंगनवाड़ी में पोषण आहार का बड़ा ठेका वर्षों तक दिया गया जिसका कोई औचित्य नहीं था। इस पोषण आहार की जांच में इसकी क्वालिटी बहुत घटिया पाई गई। फिर भी यह अनुबंध काफी समय तक चलता रहा।

आंगनवाड़ी संचालिकाओं को उचित पारिश्रमिक समय पर मिलना चाहिए। उन पर अतिरिक्त कार्य का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। कुछ वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश में सरकार ने आंगनवाड़ी संचालिकाओं को ही साथ में आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता का अतिरिक्त कार्य भार संभालने के लिए कह दिया। अब हाल ही में वहां नई सरकार ने यह गलती सुधारते हुए हज़ारों आशा कार्यकर्ताओं की अलग से नियुक्ति करने का उचित निर्णय लिया है।

आंगनवाड़ी कार्यक्रम की सबसे बड़ी कमज़ोरी 6 महीने से 3 वर्ष की आयु के बच्चों के संदर्भ में सामने आई है। यह उम्र पोषण व स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है और इस अवधि में यदि बच्चा कमज़ोर रह जाता है तो फिर बाद में इसकी क्षतिपूर्ति कठिन होती है। पर पोषण कार्यक्रम में यही आयु वर्ग सबसे उपेक्षित हो रहा है। इतने छोटे बच्चों के लिए उचित व्यवस्था न रहने के कारण देश के बड़े हिस्से में उन्हें आंगनवाड़ी में स्थान नहीं दिया जाता है। उनके लिए थोड़ा-सा राशन उनकी मां को घर ले जाने के लिए दे दिया जाता है जो कुपोषण दूर करने के लिए अपर्याप्त साबित होता है।

इस स्थिति में या तो आंगनवाड़ी में सुधार कर इस नाज़ुक आयु वर्ग के बच्चों की व्यवस्था करनी चाहिए या इस आयु वर्ग के लिए अलग से झूलाघर की व्यवस्था करनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में झूलाघर अभी बहुत कम हैं, पर जहां ये अच्छी तरह चलाए गए हैं, जैसे राजस्थान के अजमेर ज़िले व छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले के कुछ गांवों में, वहां इनके उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए हैं। ***(स्रोत फीचर्स)***